

MASTER OF ARTS (HISTORY) (MAHI)

Term-End Examination December, 2024

MHI-105 : HISTORY OF INDIAN ECONOMY

MOST IMPORTANT QUESTIONS FOR EXAM

आसान भाषा में समझें।

1. Write a note on Indian economy during 1800-1857.

Indian Economy During 1800-1857

The period between 1800 and 1857 was a crucial phase in Indian economic history, marked by the consolidation of British colonial rule. The economic landscape of India underwent profound changes during this time, with the introduction of British economic policies and systems that significantly altered the agrarian structure and industrial landscape.

1800 और 1857 के बीच का काल भारतीय आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था, जो ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के सुदृढ़ीकरण का समय था। इस अवधि के दौरान भारत की आर्थिक संरचना में गहरे परिवर्तन हुए, जिनमें ब्रिटिश आर्थिक नीतियों और प्रणालियों का परिचय दिया गया, जिसने कृषि संरचना और औद्योगिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया।

1. Decline of Traditional Industries

During British rule, traditional industries like textiles, handicrafts, and metal works faced a severe decline. The British imported manufactured goods to India, and their cheap, mass-produced goods undermined local industries, leading to their collapse. Indian artisans and craftsmen, who had once been renowned for their skill, were left without work.

Example: The Indian handloom textile industry, which had flourished for centuries, was crippled as British textiles flooded the market, driving local craftsmen out of business.

1. पारंपरिक उद्योगों का गिरना

ब्रिटिश शासन के दौरान पारंपरिक उद्योगों जैसे कपड़ा, हस्तशिल्प, और धातुकर्म में भारी गिरावट आई। ब्रिटिशों ने भारत में निर्मित वस्तुओं का आयात किया, और उनके सस्ते, बड़े पैमाने पर उत्पादित सामानों ने

स्थानीय उद्योगों को कमजोर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप इनका पतन हुआ। भारतीय कारीगर और शिल्पकार, जो कभी अपनी कला के लिए प्रसिद्ध थे, अब काम से वंचित हो गए।

उदाहरण: भारतीय हथकरघा उद्योग, जो सदियों से समृद्ध था, ब्रिटिश वस्त्रों के बाजार में आने से कमजोर पड़ गया, जिससे स्थानीय कारीगरों को काम नहीं मिला।

2. Agrarian Economy

India during the early 19th century was primarily an agrarian economy. The British introduced land revenue systems like the **Permanent Settlement** (1793) in Bengal and **Ryotwari** in the south to extract revenue from land. These policies often placed heavy tax burdens on the peasants, leading to widespread poverty, debt, and sometimes even famines.

Example: The **Permanent Settlement** in Bengal fixed land revenue at a fixed rate, which made the zamindars (landlords) responsible for collecting taxes, leading to exploitation of farmers and a rise in absentee landlordism.

2. कृषि आधारित अर्थव्यवस्था

19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत मुख्य रूप से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था। ब्रिटिशों ने **स्थायी बंदोबस्त** (1793) जैसे भूमि राजस्व प्रणाली और दक्षिण भारत में **रायटवारी** प्रणाली लागू की, जिससे भूमि से राजस्व निकाला गया। इन नीतियों ने किसानों पर भारी कर बोझ डाला, जिसके कारण व्यापक गरीबी, कर्ज और कभी-कभी अकाल भी आए।

उदाहरण: **स्थायी बंदोबस्त** ने बंगाल में भूमि राजस्व को एक निश्चित दर पर निर्धारित किया, जिससे जमींदारों (भूमि मालिकों) को कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके कारण किसानों का शोषण हुआ और अनुपस्थित जमींदारों की संख्या में वृद्धि हुई।

3. Commercialization of Agriculture

The British introduced the cultivation of commercial crops like indigo, cotton, and opium. These crops were grown primarily for export to European markets, which changed the nature of Indian agriculture. Farmers were often forced to grow these crops at the expense of food production, leading to food shortages and famines in several regions.

Example: The cultivation of indigo in Bengal is a well-known example where farmers were forced to grow indigo for export, which led to economic distress and rebellion.

3. कृषि का व्यापारीकरण

ब्रिटिशों ने वाणिज्यिक फसलों जैसे नील, कपास, और अफीम की खेती को बढ़ावा दिया। ये फसलें मुख्य रूप से यूरोपीय बाजारों के लिए उगाई जाती थीं, जिससे भारतीय कृषि का स्वरूप बदल गया। किसानों को अक्सर खाद्य उत्पादन के बदले इन फसलों की खेती करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके कारण कई क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी और अकाल पड़े।

उदाहरण: बंगाल में नील की खेती एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जहाँ किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे आर्थिक संकट और विद्रोह हुआ।

4. Rise of the Zamindari System and Exploitation

Under the **Permanent Settlement**, zamindars (landlords) were given control over land and made responsible for collecting taxes. However, this led to the exploitation of peasants, as the zamindars were often absentee landlords who imposed high taxes, leading to the suffering of farmers. The introduction of the system worsened the economic condition of the peasantry and made them vulnerable to debt and poverty.

Example: In Bengal, many peasants lost their land and were pushed into debt because of the high taxes imposed by zamindars under the Permanent Settlement.

4. जमींदारी प्रणाली का उदय और शोषण

स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों (भूमि मालिकों) को भूमि का नियंत्रण सौंपा गया और उन्हें कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि, इससे किसानों का शोषण हुआ, क्योंकि जमींदार अक्सर अनुपस्थित रहते थे और उच्च कर लगाते थे, जिसके कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस प्रणाली ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और भी खराब किया और उन्हें कर्ज और गरीबी का शिकार बना दिया।

उदाहरण: बंगाल में, कई किसानों ने उच्च करों के कारण अपनी ज़मीन खो दी और वे जमींदारों द्वारा लगाए गए करों के चलते कर्ज में डूब गए।

5. Infrastructure Development

The British focused on building infrastructure in India primarily for their own economic benefit. Railways, roads, and ports were constructed to facilitate the movement of goods, especially raw materials, to the ports for export to Britain. This infrastructure, however, did little to help the Indian economy, as it was largely designed to serve British colonial interests.

Example: The development of the railway network primarily aimed at facilitating the export of raw materials like cotton and jute to Britain, rather than improving the economic situation of Indians.

5. बुनियादी ढांचे का विकास

ब्रिटिशों ने भारत में बुनियादी ढांचे का निर्माण मुख्य रूप से अपनी आर्थिक लाभ के लिए किया। रेलवे, सड़कें और बंदरगाह इस उद्देश्य से बनाए गए थे ताकि माल, खासकर कच्चे पदार्थों को ब्रिटेन के लिए बंदरगाहों तक पहुँचाया जा सके। हालांकि, यह बुनियादी ढांचा भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक लाभ नहीं पहुंचा सका, क्योंकि यह ज्यादातर ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की सेवा के लिए था।

उदाहरण: रेलवे नेटवर्क का विकास मुख्य रूप से कच्चे माल जैसे कपास और जूट को ब्रिटेन भेजने के लिए था, न कि भारतीयों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए।

2 Analyse the nature of Indian economic growth in the first three Five Year Plans.

India's economic growth during the first three Five Year Plans (1951–1966) had a mix of achievements and challenges.

These plans were designed to modernize India's economy, with an emphasis on industrialization, infrastructure development, and improving agriculture.

पहली तीन पाँच वर्षीय योजनाओं (1951-1966) के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि में उपलब्धियाँ और चुनौतियों दोनों का मिश्रण था। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाना था, जिसमें औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और कृषि सुधार पर जोर दिया गया था।

1. First Five Year Plan (1951-1956)

The First Five Year Plan focused mainly on agricultural development and infrastructure, aiming to increase food production and establish basic infrastructure for long-term economic growth.

1. पहले पाँच वर्षीय योजना (1951-1956)

पहली पाँच वर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि विकास और बुनियादी ढांचे पर था, ताकि खाद्य उत्पादन बढ़े और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार हो सके।

Key Features:

- **Agriculture Focus:** The plan focused on improving agricultural production through better irrigation, land reforms, and the use of new techniques. The goal was to ensure food security and raw materials for industries.
- **Infrastructure Development:** The plan prioritized building irrigation facilities, power plants, roads, and railways to lay a strong foundation for future growth.
- **Public Sector Investment:** Limited investment was made in sectors like power, transport, and communication.

मुख्य विशेषताएँ:

- **कृषि पर ध्यान:** योजना का मुख्य उद्देश्य बेहतर सिंचाई, भूमि सुधार और नई तकनीकों के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। उद्देश्य था खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करना।
- **बुनियादी ढांचा विकास:** योजना ने सिंचाई सुविधाओं, पावर प्लांट, सड़कों और रेलवे का निर्माण प्राथमिकता से किया ताकि भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी जा सके।
- **सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश:** बिजली, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों में सीमित निवेश किया गया।

Growth Analysis:

- **Agricultural Growth:** There was modest growth in agriculture, especially in regions where irrigation projects were introduced. However, natural disasters, like floods, reduced the expected gains.
- **Industrial Growth:** Industrial growth was slow due to a lack of capital, and industrial infrastructure was not fully developed.
- **Overall Growth:** The economy grew by 3.6%, slightly above the target of 2.1%, but poverty remained widespread, and the benefits of growth were uneven.

विकास का विश्लेषण:

- **कृषि विकास:** कृषि में मामूली वृद्धि हुई, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई थीं। हालांकि, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ ने अपेक्षित वृद्धि को प्रभावित किया।
- **औद्योगिक विकास:** औद्योगिक विकास धीमा था, क्योंकि पूंजी की कमी थी और औद्योगिक बुनियादी ढांचा पूरी तरह से विकसित नहीं था।
- **कुल विकास:** अर्थव्यवस्था ने 3.6% की वृद्धि की, जो 2.1% के लक्ष्य से थोड़ा अधिक था, लेकिन गरीबी व्यापक बनी रही और विकास के लाभ असमान थे।

2. Second Five Year Plan (1956-1961)

The Second Five Year Plan focused on industrialization, particularly heavy industries, and was influenced by the Mahalanobis Model, which emphasized public sector investment in key sectors.

2. दूसरी पाँच वर्षीय योजना (1956-1961)

दूसरी पाँच वर्षीय योजना का ध्यान औद्योगिकीकरण पर था, विशेष रूप से भारी उद्योगों पर, और यह महलनॉबिस मॉडल से प्रभावित थी, जो सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देता था।

Key Features:

- **Industrialization and Heavy Industries:** The plan aimed to establish large-scale industries like steel, machinery, and chemicals. It focused on reducing dependence on foreign imports and boosting self-reliance in manufacturing.
- **Public Sector Investments:** A major emphasis was placed on the development of the public sector, with private sector involvement kept to a minimum.
- **Infrastructure Expansion:** The plan also called for increased investments in transport and energy sectors to support industrial growth.

मुख्य विशेषताएँ:

- **औद्योगिकीकरण और भारी उद्योग:** योजना का उद्देश्य स्टील, मशीनरी और रसायन जैसे बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित करना था। इसका उद्देश्य विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना और निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाना था।

- **सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश:** सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया, जबकि निजी क्षेत्र की भागीदारी को न्यूनतम रखा गया।
- **बुनियादी ढांचे का विस्तार:** योजना में परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का समर्थन करने के लिए निवेश बढ़ाने की आवश्यकता जताई गई।

Growth Analysis:

- **Industrial Growth:** Significant progress was made in establishing industries, with new steel plants and other heavy industries coming up, especially in areas like Bhilai and Bokaro.
- **Agricultural Growth:** The industrial focus led to neglect in agriculture, which continued to stagnate during this plan.
- **Overall Growth:** The economy grew at 4.27% annually, which was better than the first plan, but still below the target. The plan faced inflationary pressures due to high public spending.

विकास का विश्लेषण:

- **औद्योगिक विकास:** उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, और नई स्टील मिलों और भारी उद्योगों का निर्माण हुआ, विशेष रूप से भिलाई और बोकारो जैसे क्षेत्रों में।
- **कृषि विकास:** औद्योगिकीकरण पर जोर देने से कृषि की अनदेखी हुई, और इस योजना के दौरान कृषि में विकास रुक गया।
- **कुल विकास:** अर्थव्यवस्था ने वार्षिक 4.27% की वृद्धि की, जो पहली योजना से बेहतर था, लेकिन फिर भी लक्ष्य से कम था। योजना उच्च सार्वजनिक खर्च के कारण मुद्रास्फीति का सामना कर रही थी।

3. Third Five Year Plan (1961-1966)

The Third Plan aimed at achieving self-sufficiency in food production, balancing industrial and agricultural growth, and addressing defense needs due to external threats.

3. तीसरी पाँच वर्षीय योजना (1961-1966)

तीसरी पाँच वर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना, औद्योगिक और कृषि विकास का संतुलन स्थापित करना, और बाहरी खतरों के कारण रक्षा जरूरतों को पूरा करना था।

Key Features:

- **Self-Sufficiency in Agriculture:** The focus was on the Green Revolution, which aimed to increase food production through high-yielding seeds, fertilizers, and modern farming techniques.

- **Balanced Growth:** The plan sought to balance industrial and agricultural growth, with a continued focus on food security.
- **External Crises:** The Indo-China war (1962) and the Indo-Pakistan war (1965) diverted resources toward defense, affecting the economic progress of the plan.

मुख्य विशेषताएँ:

- **कृषि में आत्मनिर्भरता:** ध्यान ग्रीन रिवोल्यूशन पर था, जिसका उद्देश्य उच्च उपज वाली किस्मों, उर्वरकों और आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से खाद्य उत्पादन बढ़ाना था।
- **संतुलित विकास:** योजना ने औद्योगिक और कृषि विकास के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें खाद्य सुरक्षा पर लगातार ध्यान दिया गया।
- **बाहरी संकट:** भारत-चीन युद्ध (1962) और भारत-पाकिस्तान युद्ध (1965) ने रक्षा पर संसाधनों को मोड़ दिया, जिससे योजना के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ा।
-

Growth Analysis:

- **Agricultural Growth:** The Green Revolution brought increased productivity in crops like wheat and rice, especially in northern India. However, the benefits were not widespread across the country.
- **Industrial Growth:** Industrial growth continued but was slower than expected due to resource diversion for defense and the overall slow pace of industrialization.
- **Overall Growth:** The economy grew at 2.8%, which was below the target of 5.6%. External challenges, poor monsoons, and increased defense spending affected the economic growth.

विकास का विश्लेषण:

- **कृषि विकास:** ग्रीन रिवोल्यूशन ने गेहूं और चावल जैसी फसलों में उत्पादकता बढ़ाई, विशेष रूप से उत्तर भारत में। हालांकि, इसका लाभ पूरे देश में समान रूप से नहीं फैला।
- **औद्योगिक विकास:** औद्योगिक विकास जारी रहा, लेकिन रक्षा के लिए संसाधन समर्पित करने और औद्योगिकीकरण की धीमी गति के कारण यह अपेक्षाकृत धीमा था।
- **कुल विकास:** अर्थव्यवस्था ने 2.8% की वृद्धि की, जो 5.6% के लक्ष्य से कम था। बाहरी चुनौतियों, खराब मानसून और बढ़ी हुई रक्षा खर्च ने आर्थिक विकास को प्रभावित किया।